REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 10 | JULY - 2024

भारत की शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के गुणवत्ता स्तर को बनाये रखने में आने वाली समस्यायें एवम् समाधान।

मि. दिनेश कुमार[1] , डॉ. राहुल गुप्ता[2]
[1]रिसर्च स्कॉलर , आई. आई. एम. टी. विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश.
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, दीवान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एनएच–58 मेरठ, उत्तर प्रदेश.

सारांश

माध्यमिक शिक्षा जो कि बहुसंख्यक नागरिकों के लिये हमारे शिक्षाक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, को यथाशीघ्र सर्वसुलभ और समान रूप से सशक्त व गुणवत्तापूर्वक बनाना न सिर्फ व्यक्ति और समाज के हित में है बल्कि यह देश के हित में भी है, अतः इसे हमारा राष्ट्रीय दायित्व समझते हुये इसका सार्वजनीकरण करना तथा इसमें गुणात्मकता पैदा करने के लिये सार्थक प्रयास किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ताप्रद माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिये वर्ष 2009 में शुरू किये गये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0 एम0 एस0 ए0) के तहत माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक के प्रत्येक स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच और वर्ष 2020 तक इसका सार्वभौमिक अवधारण प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया था। महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के बावजूद, यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यद्यपि वर्ष 2020 में जारी भारत की नवीनतम् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई थी। इसमें 2030 तक सभी स्तरों पर गुणवत्ता स्तरों को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की आवश्यकता को दोहराया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच की परिकल्पना की गई है। हालांकि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन अधिक होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच कम रही है। संभवतः जिसके अनेकों कारणों में से माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की सीमित संख्या, विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी लागत और शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण में सार्वजनिक निवेश की कमी जैसे अनेकों कारण हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है, कि देश में माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये और इसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करते हुये केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की शिक्षा योजना में इसे प्राथमिकता देकर अधिक नीतिगत करने का समय आ गया है। अतः सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पर्याप्त शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और एक जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस दिशा में जब तक कठोर उपाय नहीं किये जाते, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक स्तर की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना अप्राप्य ही लगता है।

शब्द कुंजी: अवधारण, सार्वभौमिक, नीतिगत, पारदर्शी तथा अप्राप्य।

प्रस्तावना

अधिकांश भारतीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम रटने पर आधारित है, जो समझने के बजाय याद करने पर केंद्रित है। इससे प्रायः यह देखने में आया है कि विद्यार्थी में आलोचनात्मक सोच कौशल की कमी हो जाती है और विद्यार्थियों द्वारा जो कुछ भी सीखा जाता है उसे वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना कठिन हो जाता है। चूंकि शिक्षा प्रत्येक समाज में विवेक, ज्ञान, समझ, और समर्पण की भावना को विकसित करती है और मानवीय सम्पदा को वृद्धि देती है साथ ही सभी क्षेत्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागु हुआ तो यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार बन गया। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को भी चलाया गया। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी है, जिनमें इस क्षेत्र में संबंधित और ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सकें। हम जानते हैं कि मानव विकास का मूल शिक्षा में ही है जो देश के सामाजिक व आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। इसी संदर्भ में विभिन्न समयांतरालों पर हमारी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों के द्वारा नित नयी जिम्मेदारियों को महसूस किया गया है और जहॉ तक संभव हुआ है विभिन्न प्रयास भी किये गये हैं, तथापि इतने संघर्षो के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख सका। हम जानते हैं कि भारत में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अथवा किसी भी स्तर की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिये सर्वाधिक सरकारी कर्मचारियों की संख्या शिक्षा विभाग में ही देखने को मिलती है, और इसमें न सिर्फ शिक्षा को प्रदान करने वाले शिक्षकों की ही आवश्यकता है वरन लाखों कर्मचारी और अधिकारी भी हैं जो इस व्यवस्था को संभालने में अपनी भूमिका को निभाने का काम बखुबी कर रहे हैं। लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों आयोगों एवम् नीतियों के लागू होने के बाद भी वांछित परिणामों का हासिल नहीं किया जा सका है। संभवतः इसका कारण इस क्षेत्र में अनेकों सांस्थानिक, प्रशासनिक एवम् आर्थिक समस्याओं का पाया जाना है। माध्यमिक शिक्षा जो बहुसंख्यक नागरिकों के लिये शिक्षाक्रम में अंतिम पड़ाव का कार्य करती है, को यथाशीघ्र, सर्वसुलभ और समान रूप से सशक्त व गुणवत्तापरक बनाना व्यक्ति, समाज और देश के हित में है, अतः माध्यमिक शिक्षा को हमारा राष्ट्रीय दायित्व समझते हुये इसके सार्वजनीकरण एवं गुणात्मकता स्तर को बढ़ाने हेतु हमें सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचक

शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। विभिन्न मान्यताएं और मूल्य लोकतंत्र में शिक्षा की धारणा को आधार बनाते हैं, इसलिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अभ्यर्थी की क्षमता को अधिकतम करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं। क्योंकि यह न सिर्फ विद्यार्थी की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक है बल्कि इसके माध्यम से बहुमुखी प्रतिभाओं को खोजने को संभव बनाया जा सकता है। इस धारणा में नवाचार' शब्द भी बहुत प्रमुख है। अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक परिभाषा यह भी है कि कुछ ऐसा हो जो कि पहले से कुछ भिन्न हो। अगर शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करने के कारकों के विषय में देखें तो इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं –

- शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संचार कौशल,
- शिक्षण विधि
- शिक्षक प्रशिक्षण
- शिक्षक का व्यक्तित्व
- कक्षा का परिवेश
- श्रव्य–दृश्य सहायक सामग्री
- शिक्षकों के वेतन, भत्ते इत्यादि

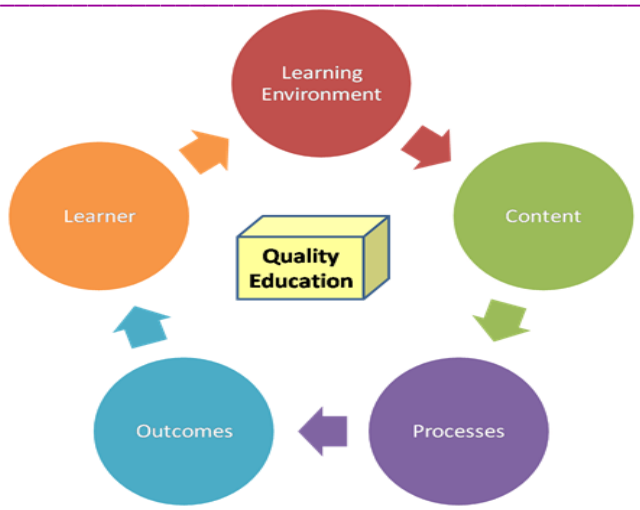

शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों में **संचार कौशलों** को प्रयुक्त किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यह वह क्षमताएं और तकनीकें हैं जो सूचना, विचार और भावनाओं को प्रभावी ढंग से संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में, संचार कौशल वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रभावी संचार से न सिर्फ प्रत्येक पक्ष लाभान्वित होता है अपितु यह रिश्तों को बेहतर बनाने, समझ बढ़ाने और सकारात्मक बातचीत का मॉडल तैयार करने में मदद करता है। **शिक्षण विधियों** के प्रयोग की बात करे तो इससे न सिर्फ छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव लाया जा सकता हैं बल्कि प्राप्त ज्ञान को समय आने पर स्मरण करना, प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करना, छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण आदि करना है। शिक्षा की तुलना में **प्रशिक्षण** के विशेष उद्देश्य होते हैं। सामान्य रूप में शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के विचार, मनोभाव और मानसिकता को उदार बनाना है, परन्तु प्रशिक्षण का लक्ष्य किसी विशेष कार्य अथवा व्यवसाय के लिए अपेक्षित विशिष्ट कार्यकुशलता और ज्ञान में सुधार करना है। जब शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है, तो यह उन्हें निरंतर व्यावसायिक विकास का अवसर देता है – नए तरीके, रणनीतियाँ, कौशल और उपकरण आदि के बारे में सीखने का। प्राचीन काल से आज तक शिक्षक को समाज के आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारा जाता है। शिक्षण में सफलता के लिए **आकर्षक व्यक्तित्व** का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। छात्रों की रुचि मापने के अलावा, यह शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों से जुड़ने, और विभिन्न विषयों को समझाने के नए तरीकों के बारे में सोचने में सक्षम बनाता है, शिक्षक ही बालकों की योग्यता, क्षमता, रूचि, अभिरूचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण की गतिविधियां उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं, जब वे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यावहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ने में सक्षम हो सके या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ सके। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अग्रसर करने के लिए पहल करनी होती है ताकि विद्यार्थियों को घनिष्ठ रूप से संबद्ध किया जा सके, और कक्षा में उपयुक्त **भौतिक परिवेश** को निर्मित्त किया जा सके। विषय–वस्तु को रोचक एवं आकर्षक बनाना विद्यार्थियों को नवीन विषय–वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए उसे रोचक एवं आकर्षक बनाने हेतु इसकी आवश्यकता प्रदान करें तो गंभीर तथा कठिन विषय–वस्तु को विद्यार्थी आसानी से समझ लेते हैं तथा उससे रुचि भी लेते हैं। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता से न सिर्फ शिक्षण प्रभावशाली होगा बल्कि शिक्षण उददेश्यों की प्राप्ति में भी यह अत्यन्त सहायक रहेगा।

माध्यमिक स्तर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने में आने वाली समस्यायें.

- हमारे देश के विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। देश भर के विद्यालयों में लगभग दस लाख से अधिक शिक्षण हेतु पद खाली हैं। यह कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है, जहां लगभग दो–तिहाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है।
- भारत में माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम–आधारित न होकर परीक्षा–उन्मुख है।

- 2016 की वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, भारत में 3.5 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं थी, जबकि केवल 68.7 प्रतिशत स्कूलों में उपयोग योग्य शौचालय की सुविधा थी। 2016 में सर्वेक्षण में शामिल 75.5 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालय थे, जो 2014 में 78.1 प्रतिशत से कम है। लड़कियों के लिए अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत 2010 में 32.9 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 61.9 प्रतिशत हो पाया है।
- 2022 की वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, भारत में अगर नामांकन की बात करें तो कुल मिलाकर 14–18 आयु वर्ग के 86.8 प्रतिशत बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 वर्षीय किशोरों के लिये 3.9 प्रतिशत और 18 वर्षीय किशोरों के लिये 32.6 प्रतिशत है, जो कि इतने प्रयास करने के बाद भी पर्याप्त नहीं लगता।
- भारतीय शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है और समाज के लिए दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम पैदा कर रहा है।
- प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत में निजी कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा दिया है। ये कोचिंग संस्थान छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, बैंकिंग नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं।
- हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। बहुत कम लड़कियाँ स्कूलों में नामांकित होती हैं, और उनमें से कई स्कूल छोड़ देती हैं। भारतीय परिवार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम दर्जा और कम विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
- भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, समस्या समाधान के बजाय, रटने पर आधारित होने के लिए आलोचना की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा और सशक्तीकरण

शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्त्व है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तेजी से हुए परिवर्तन तथा जीवन–स्तर को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने की आवश्यकता के मद्देनजर यह जरूरी है कि विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल में ऊँचा स्तर प्राप्त हो। इसके लिये माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना में विभिन्न शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुचारू रूप में हो ताकि लोगों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को स्कूल–पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में बाँटा है ताकि इसकी निरंतरता लगातार बनी रह सके। योजना का उद्देश्य अंग्रेजी के टीचर्स और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बाँटे बिना स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति के परिणामों पर आधारित है। योजना में सभी हितधारकों– माता–पिता, अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, समुदाय तथा राज्यकर्मी आदि की सक्रिय भागीदारी होती है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। इसी सन्दर्भ में गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को रोचक और लोकप्रिय बनाने के क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय अविष्कार अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विद्यालयों के पास आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से परामर्शदाता के तौर पर अनुभव प्राप्त करने के अवसर होते हैं। अतः प्रारंभ किए गये अटल अभिनव अभियान और अटल टिंकरिंग लैब से छात्रों के बीच महत्वपूर्ण विश्लेषण, सृजनात्मकता और समस्या को सुलझाने जैसी गतिविधियों को बल मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य कहीं भी किसी भी समय उच्च शैक्षिक संस्थानों में सभी विद्यार्थियों के लाभ हेतु शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पूर्ण इस्तेमाल करना है। इस मिशन के दो प्रमुख अंग हैं– संस्थानों और विद्यार्थियों को पहुँच प्रदान करने के साधनों को जोड़ना और विषयवस्तु सृजन। इसके अतिरिक्त इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देशभर में विद्यार्थियों को ई–सामग्री के रूप में सुलभ ज्ञान उपलब्ध कराना है। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति अयोग ने एक राज्य–स्तरीय स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक बनाया है, जो सीखने के परिणामों में सुधार के एक केंद्र बिंदु का काम करता है। यह राज्यों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिये दिये गए अंकों के आधार पर रैंकिंग देता है। यह रैंकिंग न केवल राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है, बल्कि अन्य राज्यों को भी लगातार सुधार करने के लिये प्रेरित करती है।

समाधान

- शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा में जीवन मूल्यों और रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा। हमें विद्यालय के आधारभूत संरचनात्मक ढांचे को आधुनिक सुविधा युक्त बनाने के साथ–साथ शिक्षकों को व्यावहारिक स्तर पर भी प्रशिक्षण देना होगा। प्रशासन एवं श्रेष्ठ विद्यालयी तंत्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में ईमानदारी से रूचि रखने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिये विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता को प्राथमिकता के तौर पर लाना होगा।
- शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सरकारों का ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, शिक्षाविदों को पूर्ण रूप से उसमें कार्य करने देना चाहिए, साथ ही हमें राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर व प्रांत स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये अपनी ओर से बेहतर योगदान करना होगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। देश के शिक्षासंबंधी सभी अध्ययन और सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का स्तर भी अपेक्षा से नीचे है। इसके लिये सीधे शिक्षकों को दोषी ठहरा दिया जाता है और इस वास्तविकता से आँखें मूँद ली जाती हैं कि विद्यालयों का बुनियादी ढाँचा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहद कमजोर है। देश में अनेंकों ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक की उपलब्धता है। आजादी 72 वर्ष बाद भी यदि देश में शिक्षा की यह दशा और दिशा है तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक होगा। इस

अभियान में सरकार, नागरिक समाज संगठन, विशेषज्ञों, माता–पिता, सामुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी।

- इसके अलावा, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की जरूरत है। अभी शिक्षण की विधियाँ राज्य स्तर से तय की जाती हैं, जिनमें कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है। शिक्षकों के अच्छे प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण का दायित्व कर्त्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिये। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी पद्धतियों का विकास करने सहित परीक्षण व मूल्यांकन की नवीन व व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिये।
- हमें क्या मूल्यांकन करना है, छात्र अपने अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं और इसके साथ–साथ शिक्षा के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में व्यवस्था का निष्पादन कैसा है, मूल्यांकन पर आधारित कक्षा के साथ व्यापक स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण को जानना, की भी आवश्यकता होती है। सरकार ने एक प्रक्रिया की पहल की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक प्रायोजन निर्धारित अध्ययन लक्ष्यों की तुलना में छात्रों के प्रदर्शन को समझने के लिए विद्यालयों को एक अवसर प्रदान करना है। इस तरह के सर्वेक्षण से शिक्षण परिणामों को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक परिवेश तैयार हो सकेगा। शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रियाएं शीघ्रता से मिलेगी ताकि वे शिक्षण अंतरालों के समाधान के लिए समय से कार्रवाई कर सके।
- आज हम विद्यालयों को मात्र इमारतों और कक्षाओं के रूप में ही नहीं देखते हैं, एक स्कूल में मूल शिक्षण स्थितियों के साथ–साथ इसमें बिजली की व्यवस्था, कार्यात्मक प्रयोगशाला और पाठन स्थल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कम्पयूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय और मध्याह्न भोजन को पकाने के लिए एलपीजी कनेक्शन भी अवश्य होना चाहिए। सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों को सलाह दी जा चुकी है कि वह वर्तमान वर्ष में सभी माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था की सुनिश्चित करें
- एक व्यापक और विविधता से भरे देश में निर्णय लेना और जवाबदेही का विकेन्द्रीकरण ही सफलता की कुंजी है। विद्यालय शिक्षा के मामले में समुदाय विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए विद्यालय समितियों को मजबूत किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि वे बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय की जवाबदेही पर भी अपना नियंत्रण कर सके। माता–पिताओं और एसएमसी सदस्यों को कक्षावार शिक्षण लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। एसएमसी बैठक, सामाजिक अंकेक्षण अथवा विद्यालय शिक्षा पर ग्रामसभा बैठकों जैसे प्रयासों को भी विद्यार्थी के अध्ययन में जोड़ने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता–पिता और समुदाय के सदस्य आगे कदम बढ़ाते हुए अपने बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालयों की जवाबदेही पर नियंत्रण बना सकते हैं इसके लिए भाषा को आसानी से समझने के लिए शिक्षण लक्ष्यों को कक्षावार तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विद्यालयों के साथ–साथ इसके व्यापक प्रचार–प्रसार को प्रदर्शित करने की भी योजना है।

निष्कर्ष

भारत में स्कूल जाने वालों की आयु 6–18 वर्ष के मध्य की एक विशाल जनसंख्या है, यदि बच्चों को वास्तविक दुनिया का आत्मविश्वास से सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में इस जनसांख्यिकीय हिस्से की संपूर्ण सामर्थ्य का अपने लिये उपयोग करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक उद्बोधन (मन की बात) में गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुये कहा था कि, अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान, शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। हम जानते हैं कि राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ने आरम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में यथेष्ट सफलता पाई है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिये केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष कार्यक्षेत्रों जैसे कि अध्यापकों की समस्याओं, कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली

कार्यविधियों, छात्रों में ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण की तकनीकों में बदलाव, विद्यालयी अवसंरचना, विद्यालयी प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया जाना है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- http://bhajanfoundation.org/knowledge/empowerment-through-education/
- https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/education-quality-in-india-challenges-and-solutions
- https://educationmirror.org/2017/03/24/main-problem-of-madhyamik-education-in-india/
- https://www.yourarticlelibrary.com/education/secondary-education
- https://e-gyan-vigyan.com/maadhyamik-shiksha-mein-gunavatta-se-sambandhit-mudde/
- **Jain,Charu and Prasad, Narayan.** "Quality of Secondary Education in India" **(**Springer**, 2018), 978-981-10-4929-3**
- पाठक, पी0 डी0. ''भारतीय शिक्षा ओर उसकी समस्याऐं'' (आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन, 2012)
- कपूर, अरूण. ''बदलते विद्यालय तेजस्वी बच्चे'' (दिल्लीः हिन्द पाकेट बुक्स, 2009)
- **अग्निहोत्री, आर. (2013)**. आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्या एवं समाधान, जयपुर, इण्डिया :राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।